

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले-यातायात ढांचे को सुदृढ़ और सुचारु बनाने के लिए 22.14 करोड़ रुपये की दी गई मंजूरी

तैयारी: पटना की सड़कों और मजबूत, चौड़ी बननेगी

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। पटना में सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकार ने 22.14 करोड़ रुपये से अधिक महत्वपूर्ण योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। शहर में यातायात को सुचारु बनाने के लिए कई मुख्य सड़कों को चौड़ा और मजबूत बनाया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बताया कि राजधानी पटना के यातायात ढांचे को सुदृढ़ और सुचारु बनाने के लिए यह मंजूरी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि यह योजना पटना के यातायात को व्यवस्थित करने और सड़कों की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

■ नया एयरपोर्टर्मिनल शुरु होने से बढ़ेगा यातायात का दबाव

■ लोक वित्त समिति और स्थायी वित्त समिति ने की है अनुशंसा

राजधानी पर यातायात का दबाव बढ़ने वाला है। जेपी गंगा पथ का लगातार विस्तार होने से भी शहर की सड़कों को चौड़ा करने और मजबूत बनाने की जरूरत महसूस की गई। इस लिए लोक वित्त समिति और स्थायी वित्त समिति ने



पटना कलेक्ट्रेट में गुरुवार को जिला अनुश्रवण समिति की बैठक को संबोधित करते उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। साथ में सांसद डॉ. भीम सिंह, पटना के डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह, नगर निगम के आयुक्त अनिमेष पराशर। • हिन्दुस्तान

विदेकानंद मार्ग, बोरिंग रोड से लेकर पश्चिम बोरिंग केनाल रोड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर तक तथा बीच में आने वाले इंदिरा सिन्हा पथ, राजेन्द्र पथ, वीर शिवाजी पथ, वीर कुंवर सिंह पथ, रामकृष्ण पथ, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, मंदर टेरेसा मार्ग, तिलक मार्ग, कस्तूरबा पथ

पटना की सड़क विकास योजना की अनुशंसा की। डीएलपी की समाप्ति के बाद ही नया कार्य शुरू होगा: उपमुख्यमंत्री श्री चौधरी ने बताया कि किसी अन्य डीएलपी की समाप्ति के बाद ही नया विभाग से अधिग्रहित पथों पर कार्यतभी कार्य शुरू किया जाएगा।

तेज विकास को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों में हो समन्वय

पटना, प्रधान संवाददाता। उप मुख्यमंत्री सह पटना जिला के प्रभारी मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के बीच समन्वय और सुदृढ़ संवाद की आवश्यकता है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति और संभावित बाढ़ की पूर्व तैयारियों को लेकर उन्होंने बैठक की।

उन्होंने सर्वप्रथम संभावित बाढ़ से संबंधित मुख्य बिंदुओं की समीक्षा की और अद्यतन प्रगति का जायजा लिया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संभावित बाढ़ एवं जलजमाव से निपटने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्धारित एसओपी के अनुसार जिलास्तर पर सभी व्यवस्था की गई है।

प्रभारी मंत्री ने एजेंडा के अनुसार विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और अद्यतन प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदिका जायजा लिया। मौके पर सांसद डॉ. भीम सिंह, विधायक अरुण सिन्हा,

■ जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक में संभावित बाढ़ की पूर्व तैयारियों पर चर्चा

योजनाओं को जल्द ही पूरा किया जाएगा

डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक लगभग 44867.02 लाख की कुल 6,443 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 5,726 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। सदस्यों से सहमति प्राप्त कर कई कारणों से 185 योजनाओं को रद्द किया गया है। डीएम ने कहा कि 532 योजनाएं प्रगति पर हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (17वीं लोकसभा) में पूर्ण योजनाओं की संख्या 427 है। इसमें 422 योजनाओं को पूरा कर लिया गया है।

ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, भाई वीरेन्द्र, डॉ. रामानन्द यादव, अनिरुद्ध कुमार, संजीव चौरसिया, रेखा देवी, गोपाल रविदास, सिद्धार्थ सोरभ आदि थे।